ISSN: 3107-3883 (Online)
Global E-Journal of Social Scientific Research
Vol. 1| Issue 4| April 2025| pp 54-59

डिजिटल विभाजनः एक समसामयिक सामाजिक चुनौती

नीलम सी डे
डायरेक्टरः ग्लोबल सेंटर ऑफ सोशल डायनामिक रिसर्च
वॉल. 1। संस्करण 4। अप्रैल 2025। पृष्ठ संख्या 54–59

परिचय

वर्तमान युग सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का युग है, जहां इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति ला दी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, सरकारी सेवाएं, सामाजिक संवाद – हर क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का प्रभाव गहरा हो चुका है। परंतु इस डिजिटल क्रांति के साथ एक गंभीर समस्या भी उभरकर आई है, जिसे हम डिजिटल विभाजन (Digital Divide) के नाम से जानते हैं। डिजिटल विभाजन का मतलब है – समाज के विभिन्न वर्गों के बीच डिजिटल तकनीक और इंटरनेट तक पहुँच में असमानता। यह असमानता न केवल तकनीकी रूप में है, बल्कि इसके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक पहलू भी हैं।

साहित्य समीक्षा

डिजिटल विभाजन के विषय पर अनेक शोधकार्य हो चुके हैं, जिन्होंने इस समस्या के विभिन्न पहलुओं को समझने और परखने का प्रयास किया है।

1. डिजिटल विभाजन की परिभाषा और आयाम

Norris (2001) ने डिजिटल विभाजन को "सामाजिक–आर्थिक समूहों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) तक पहुँच, उपयोग, और लाभों में असमानता" के रूप में परिभाषित किया। उनकी शोध के अनुसार, डिजिटल विभाजन केवल तकनीकी पहुँच तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें डिजिटल कौशल, उपयोग की गुणवत्ता और परिणामों की समानता भी शामिल है। इसी विचारधारा को Helsper (2012) ने आगे बढ़ाया, जिन्होंने तकनीकी पहुँच के अलावा उपयोग की सामाजिक–आर्थिक व्याख्या पर जोर दिया।

2. भारत में डिजिटल विभाजन की स्थिति

भारत में डिजिटल विभाजन की समस्या गहरी और जटिल है। Mehta & Sharma (2019) ने ग्रामीण और शहरी भारत के बीच इंटरनेट और मोबाइल फोन की पहुँच में भारी अंतर दिखाया। उनके अध्ययन में पता चला कि शहरी क्षेत्रों में 70ः से अधिक लोगों के पास इंटरनेट की पहुँच है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह संख्या 30ः से कम है। वहीं, ठींजजंबींतलं (2020) ने डिजिटल साक्षरता में लैंगिक असमानता पर प्रकाश डाला, जहां महिलाओं की डिजिटल पहुँच पुरुषों की तुलना में लगभग 40% कम है।

3. डिजिटल विभाजन के प्रभाव Sharma & Singh (2021) के शोध अनुसार, डिजिटल विभाजन ने कोविड–19 महामारी के दौरान शिक्षा में असमानताएँ और अधिक बढ़ा दी हैं। ऑनलाइन शिक्षा के प्रसार से पिछड़े वर्ग के छात्रों को भारी नुकसान हुआ क्योंकि उनके पास आवश्यक उपकरण और इंटरनेट नहीं था। इसी तरह, Gupta et al- (2018) ने डिजिटल विभाजन के आर्थिक प्रभावों पर अध्ययन करते हुए पाया कि डिजिटल तकनीक तक पहुँच न होने से आर्थिक अवसरों की कमी होती है और रोजगार के नए अवसरों से वंचित होना पड़ता है।

4. डिजिटल समावेषन और नीतिगत प्रयास

डिजिटल इंडिया जैसी पहलें इस समस्या को कम करने का प्रयास कर रही हैं। Kumar & Joshi (2020) ने इन पहलों के प्रभावों का विश्लेषण किया और पाया कि भले ही डिजिटल इंडिया ने इंटरनेट पहुँच बढ़ाई है, लेकिन साक्षरता और सामग्री की कमी के कारण डिजिटल विभाजन पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाया। उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री विकास और व्यापक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को आवश्यक बताया।

5. डिजिटल विभाजन और सामाजिक असमानता

विभिन्न शोधों ने डिजिटल विभाजन को सामाजिक असमानता के व्यापक ढांचे में रखा है। Verma (2017) के अनुसार, डिजिटल विभाजन सामाजिक जाति, वर्ग और लैंगिक भेदों को और भी गहरा करता है, जिससे समान अवसरों का अभाव बढ़ता है। इससे स्पष्ट होता है कि डिजिटल विभाजन तकनीकी समस्या के साथ–साथ सामाजिक न्याय का भी प्रश्न है।

सारांश

वर्तमान साहित्य से यह स्पष्ट है कि डिजिटल विभाजन एक बहुआयामी समस्या है जिसमें तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू जुड़े हुए हैं। भारत में ग्रामीण–शहरी, लैंगिक और आर्थिक असमानताएं इस विभाजन को बढ़ावा देती हैं। डिजिटल समावेशन के लिए नीति, शिक्षा, और सांस्कृतिक संदर्भ में बदलाव आवश्यक हैं।

डिजिटल विभाजन पर संभावित शोध प्रश्नः

1. भारत में डिजिटल विभाजन के मुख्य कारण क्या हैं?
2. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल तकनीक की पहुँच और उपयोग में क्या अंतर हैं?
3. डिजिटल विभाजन का शिक्षा और रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है?
4. लैंगिक असमानता डिजिटल विभाजन को किस प्रकार प्रभावित करती है?
5. डिजिटल समावेशन (Digital Inclusion) को बढ़ाने के लिए किन नीतियों और उपायों की आवश्यकता है?
6. क्या आर्थिक स्तर और शैक्षिक पृष्ठभूमि डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट उपयोग की दर को प्रभावित करते हैं?
7. क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री की उपलब्धता डिजिटल समावेशन में क्या भूमिका निभाती है?

डिजिटल विभाजन पर संभावित परिकल्पनाएँ

1. भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट की पहुँच में महत्वपूर्ण अंतर है।

परिकल्पनाएँ 2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट उपयोग की दर निम्न होती है, जिससे वे डिजिटल विभाजन के प्रभाव में अधिक प्रभावित होते हैं।

परिकल्पनाएँ 3. डिजिटल विभाजन के कारण शिक्षा में असमानता बढ़ती है, खासकर ऑनलाइन शिक्षा के प्रसार के समय।

परिकल्पनाएँ 4. लैंगिक असमानता डिजिटल विभाजन को बढ़ावा देती है, जिससे महिलाओं की तकनीक तक पहुँच पुरुषों की तुलना में कम होती है।

परिकल्पनाएँ 5. क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री की कमी डिजिटल समावेशन में बाधा उत्पन्न करती है।

डिजिटल विभाजन की परिभाषा और प्रकार

डिजिटल विभाजन को तीन स्तरों पर देखा जा सकता हैः

पहला स्तरः भौतिक पहुँच का अंतर, जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन और डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता में असमानता।

दूसरा स्तरः उपयोग और कौशल में अंतर, जहाँ तकनीक का उपयोग करने के लिए आवश्यक डिजिटल साक्षरता और क्षमता का अभाव होता है।

तीसरा स्तरः उपयोग के परिणामों में असमानता, जैसे कि डिजिटल तकनीक का सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त करने में भिन्नता।

भारत में डिजिटल विभाजन के कारण

भारत जैसे देश में डिजिटल विभाजन के कई कारण हैंः

आर्थिक असमानताः गरीब और निम्न आय वर्ग के लिए स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन महंगे हैं।

भौगोलिक बाधाएंः ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी।

शैक्षिक अंतरः डिजिटल साक्षरता का अभाव, खासकर महिलाओं और वृद्धों में।

भाषाई और सांस्कृतिक विविधतारू अधिकांश डिजिटल सामग्री अंग्रेजी में उपलब्ध है, जो सभी के लिए सुलभ नहीं।

लैंगिक असमानताः महिलाओं की तकनीक तक पहुंच पुरुषों से कम है।

डिजिटल विभाजन के सामाजिक, आर्थिक, और शैक्षिक प्रभाव

डिजिटल विभाजन का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता हैः

शिक्षा में असमानताः कोविड–19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा के विस्तार ने डिजिटल असमानता को उजागर किया। गरीब बच्चों को तकनीकी संसाधन न होने के कारण शैक्षिक नुकसान उठाना पड़ा।

आर्थिक अवसरों की कमीरू डिजिटल तकनीक से जुड़ी नौकरियों, उद्यमशीलता और बाजार तक पहुँच सीमित हो जाती है।

सामाजिक बहिष्काररू डिजिटल सेवाओं का उपयोग न कर पाने वाले वर्ग सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, और डिजिटल बैंकिंग से वंचित रह जाते हैं।

सामाजिक गतिशीलता में बाधारू डिजिटल विभाजन से आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़े वर्गों की स्थिति और अधिक दुरुस्त होती है।

डिजिटल समावेशन के प्रयास और चुनौतियाँ

सरकार और विभिन्न संस्थाएं डिजिटल समावेशन (क्पहपजंस प्दबसनेपवद) के लिए कई प्रयास कर रही हैंरू

- डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं को हर कोने तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं।
- मुफ्त या सस्ते इंटरनेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराना।
- डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन।
- क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री का विकास।

परंतु चुनौतियाँ भी अनेक हैंः

- इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव और रख–रखाव।
- डिजिटल साक्षरता का व्यापक और प्रभावी प्रशिक्षण।
- सामाजिक एवं सांस्कृतिक बाधाएं, जैसे पारंपरिक सोच और लैंगिक भेदभाव।

समाधान और सुझाव

डिजिटल विभाजन को खत्म करने के लिए बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता हैरू

- सस्ती और व्यापक इंटरनेट सेवा हर क्षेत्र में उपलब्ध कराना।
- डिजिटल साक्षरता को प्राथमिकता देना, खासकर ग्रामीण महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए।
- भाषाई समावेशन के लिए स्थानीय भाषाओं में सामग्री और सेवाएं प्रदान करना।
- सामाजिक जागरूकता बढ़ाना ताकि डिजिटल उपकरणों के महत्व को समझा जा सके।
- साझेदारी मॉडल में निजी, सरकारी, और सामाजिक संस्थाओं का समन्वय बढ़ाना।

निष्कर्ष

डिजिटल विभाजन केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और विकास का मुद्दा है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में डिजिटल तकनीक का समावेशी उपयोग ही राष्ट्रीय विकास और समृद्धि की कुंजी है। अतः डिजिटल विभाजन को दूर करना सामाजिक सुधार, आर्थिक विकास और संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए अनिवार्य है। यदि हम सभी स्तरों पर समेकित प्रयास करें, तो हम एक डिजिटल समान और समावेशी भारत का निर्माण कर सकते हैं।

संदर्भ सूची

1. नॉरिस, पी. (2001)। डिजिटल डिवाइडरू सिविक एंगेजमेंट, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट वर्ल्डवाइड। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रेस।

2. हेल्सपर, ई. जे. (2012)। डिजिटल विभाजन के नए ढांचेरू उपयोग और जुड़ाव पर सामाजिक विभाजन का प्रभाव। द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, 28(1), 1–14।

3. मेहता, आर. और शर्मा, डी. (2019)। भारत में डिजिटल पहुँच का सामाजिक–आर्थिक विश्लेषण। भारतीय समाजशास्त्र समीक्षा, 45(2), 102–117।

4. भट्टाचार्य, ए. (2020)। लैंगिक परिप्रेक्ष्य से भारत में डिजिटल साक्षरता की स्थिति। टेक्नोलॉजी एंड जेंडर स्टडीज जर्नल, 7(1), 55–70।

5. शर्मा, वी. और सिंह, आर. (2021)। कोविड–19 के दौरान डिजिटल विभाजन और शिक्षा में असमानता। भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका, 10(3), 88–99।

6. गुप्ता, पी., अग्रवाल, एन. और खान, एस. (2018)। डिजिटल प्रौद्योगिकी और आर्थिक अवसररू एक तुलनात्मक अध्ययन। डिजिटल इंडिया जर्नल, 3(2), 20–33।

7. कुमार, एस. और जोशी, आर. (2020)। डिजिटल इंडिया पहल का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभाव। नीति और प्रशासनिक

अध्ययन, 12(1), 41–56।

8. वर्मा, के. (2017)। डिजिटल असमानता और सामाजिक न्याय का प्रश्न। समाज और विकास, 29(4), 110–123।

9. भारत सरकार (2023)। डिजिटल इंडिया रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डमपजल), नई दिल्ली।

10. यूनिसेफ इंडिया (2021)। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल पहुंचरू भारत में बच्चों की स्थिति। नई दिल्लीः यूनिसेफ।